शुभ दीपावली

आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ
है कहां वह आग जो मुझको जलाए
है कहां वह ज्वाल मेरे पास आए
रागिनी तुम आज दीपक राग गाओ
आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ।

डॉ. हरिवंशराय बच्चन

न्यूज गैलरी

भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए भारत रत्न की मांग

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मरणोपरांत भारत रत्न देने की अपील की है। मनीष तिवारी ने शनिवार को एक ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत रत्न प्रदान किया जाए और चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भगत सिंह की याद में समर्पित किया जाए। उन्होंने तीनों शहीदों को शहीद-ए-आजम की उपाधि से सम्मानित करने की मांग भी की। पत्र में मनीष तिवारी ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने कठोर विरोध से देशभक्तों की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया और बाद में 23 मार्च, 1931 को अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कांग्रेस नेता ने लिखा, अगर तीनों को 26 जनवरी, 2020 को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए तो यह 124 करोड़ भारतीयों के दिलों को छूने वाला काम होगा। (आइएएनएस)

दिवाली पर जवानों से मिलने अग्रिम इलाके में जा सकते हैं पीएम

नई दिल्ली : दिवाली पर दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों से मिलने की अपनी परंपरा जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किसी अग्रिम इलाके में जा सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने 2018 में दिवाली का त्योहार उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा के निकट बर्फीले इलाके में सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ मनाया था। 2017 में प्रधानमंत्री ने दिवाली जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सैनिकों के साथ मनाई थी। 2016 में मोदी दिवाली पर हिमाचल प्रदेश में थे और उन्होंने यह त्योहार एक आउटपोस्ट पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ मनाया था। 2015 में दिवाली पर वह पंजाब सीमा पर गए थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाई थी। (प्रेट्र)

मिर्ची के मामले में शिल्पा के पति से पूछताछ करेगी ईडी

नई दिल्ली : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की संपत्तियों के सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए तलब करेगा। ईडी के मुताबिक मिर्ची की संपत्तियों का सौदा करने में अहम भूमिका निभाने वाले रणजीत सिंह बिंद्रा और कुंद्रा के बीच व्यवसायिक सौदे हुए थे। लगभग 225 करोड़ रुपये की मिर्ची की संपत्तियों के सौदे के मामले में बिंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिंद्रा की रियल एस्टेट कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसेंशल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के बीच सौदे के बारे में जानकारी मिली है। इसेंशल हॉस्पिटैलिटी में शिल्पा शेट्टी निदेशक हैं। अधिकारी के मुताबिक बिंद्रा की कंपनी ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी में 44.11 करोड़ रुपये निवेश किए थे और 31.54 करोड़ रुपये का ब्याज रहित कर्ज दिया था। शिल्पा की कंपनी को अप्रैल, 2017 से मार्च 2018 के बीच 30.45 करोड़ रुपये और अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 के बीच 117.17 करोड़ रुपये का कर्ज भी मिला था। राज से इन्हीं सौदों के बारे में पूछताछ की जाएगी। (आइएएनएस)

पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र : वेंकैया

बोले उपराष्ट्रपति ▶ दुनिया और खुद के भले के लिए आतंकवाद का रास्ता छोड़े पड़ोसी मुल्क

गुटनिरपेक्ष समूह में हम सभी का फोकस हमारे विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने पर है

बाकू (अजरबैजान), एएनआइ : पाकिस्तान को आतंकवाद का समकालीन केंद्र बताते हुए उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद को दुनिया, अपने पड़ोसियों और खुद के भले के लिए आतंकवाद को निर्णायक रूप से त्याग देना चाहिए।

गुटनिरपेक्ष देशों के 18वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद का जिक्र आते ही हमारा ध्यान सीधे इसके समकालीन केंद्र पाकिस्तान की ओर जाता है। उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की सम्मेलन के मंच का दुरुपयोग सीमापार आतंकवाद की अपनी दीर्घकालिक नीति को न्यायोचित ठहराने के लिए करने के लिए कड़ी आलोचना की। नायडू ने कहा, 'गुटनिरपेक्ष समूह में हम सभी का फोकस हमारे विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने पर है। पाकिस्तान को साफ तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास अर्जित करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है।' उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को ऐसा सबसे विनाशकारी खतरा बताया जो लगातार अपना पैर पसारता जा रहा है। उन्होंने कहा, 'इस खतरे से निपटने का सिर्फ एक मार्ग है कि आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ लड़ाई के सभी वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानूनों और तंत्र को बिना अपवाद मजबूत बनाया जाए और उन्हें लागू किया जाए।' उपराष्ट्रपति ने समूह देशों से अनुरोध किया कि वे प्रभावशाली बने रहने पर फिर फोकस करें और आतंकवाद, वैश्विक शासन सुधार, सतत विकास व सहयोग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकालें। साथ ही उन्होंने सदस्य देशों से एकजुट होकर सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का आह्वान किया क्योंकि हिंसक चरमपंथी विचारधाराओं और आतंकी कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता।

अजरबैजान की राजधानी बाकू में शनिवार को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18 वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। साथ में हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

जयशंकर ने कुवैत, बहरीन के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

बाकू (अजरबैजान), प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कुवैत और बहरीन के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। यह मुलाकात यहां चल रहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नाम) सम्मेलन से इतर हुई। दोनों खाड़ी देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है। 120 सदस्य देशों के प्रमुखों को एक मंच पर लाने के लिए शुक्रवार को दो दिवसीय नाम शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। जयशंकर ने ट्वीट किया है, 'कुवैत के विदेश मंत्री शेख सबाह खालिद अल-हमद अल-सबह के साथ मुलाकात अच्छी रही। हमारे ऐतिहासिक दोस्ताना और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का गहराई से मूल्यांकन किया गया।'

कुवैत, भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदार है। 2017-18 में कुवैत भारत के लिए नौंवा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा। उसने भारत की 4.63 फीसद ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। एक अन्य ट्वीट में जयशंकर ने कहा है, 'बहरीन के विदेश मंत्री खालिद खलीफा मिलकर अच्छा लगा।'

ममता के घर कालीपूजा में शरीक होंगे राज्यपाल धनखड़

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- जगदीप ने स्वीकार किया आमंत्रण, आज सपत्नीक होंगे शामिल
- कहा-अभिभूत हूं, मुझे और किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं

बंगाल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के रिश्तों में व्याप्त कड़वाहट के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपने घर होने वाली कालीपूजा में आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने भी कड़वाहट भुलाते हुए रविवार को सपत्नीक पूजा में शरीक होने की बात कही है। शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक काली पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों ने जब राज्यपाल से इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने कहा-'न्योता मिलने से बहुत खुश हूं और उत्सुकता से पूजा में शामिल होने का इंतजार कर रहा हूं। आशा है मुझे यहां किसी और सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा-'1978 से मुख्यमंत्री के कालीघाट स्थित आवास पर हर साल कालीपूजा का आयोजन होते आ रहा है और इसके लिए आमंत्रण मिलने से मैं अभिभूत हूं। मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर बताया था कि मैं और मेरी पत्नी भैया दूज के अवसर पर उनके घर आना चाहते हैं। इसके बाद उत्तर बंगाल की यात्रा से लौटकर मुख्यमंत्री ने मुझे पत्र लिखा और सपत्नीक काली पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।' शनिवार को राजभवन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर भी राज्यपाल के मुख्यमंत्री के घर काली पूजा में शामिल होने की पुष्टि की गई है।

जुबानी जंग बनी थीं सुर्खियां

हाल के दिनों में राज्यपाल व राज्य के मंत्रियों के बीच जुबानी जंग सुर्खियों में रही है। जादवपुर विश्वविद्यालय से लेकर दुर्गा पूजा कार्निवल, जियागंज से लेकर प्रशासनिक बैठकों से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के नदारद रहने तक को लेकर राज्यपाल व राज्य सरकार में टकराव की तौर पर देखा गया है। इन सभी मामलों को लेकर राज्यपाल ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। इसके जवाब में राज्य के मंत्रियों ने भी राज्यपाल पर पलटवार किया है।

गौरतलब है कि राज्यपाल शनिवार को बारासात के जिस क्लब में काली पूजा का उद्घाटन करने पहुंचे थे, उसके मुख्य संरक्षक और तृणमूल कांग्रेस नेता ने धनखड़ को आमंत्रित किए जाने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसे लेकर शुक्रवार को विवाद भी हुआ था।

'चिदंबरम के खिलाफ मामला काल्पनिक नहीं, गंभीर अपराध है'

नई दिल्ली, आइएएनएस : पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आइएनएक्स मीडिया घोटाले में सीबीआइ का मामला महज काल्पनिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी समीक्षा याचिका में जांच एजेंसी ने कहा है कि मामला तीन अन्य सुबूतों पर मजबूती से टिका है। इसमें गवाह इंद्राणी मुखर्जी का बयान और दुनिया भर के देशों में जमा पैसे के दस्तावेजी सुबूत हैं। आइएनएक्स मीडिया समूह को एफआइपीबी मंजूरी दिलाने के लिए धन का लेनदेन किया गया था।

सीबीआइ सूत्रों के अनुसार, 'हम उस छिपे हुए तारों की तलाश में जुटे हैं जिसमें करीब एक दर्जन देशों में विभिन्न नाम से बैंक खातों में पैसे जमा किए गए। हमारा मामला स्पष्ट और असंदिग्ध गवाहियों और सीआरपीसी की धारा 161 एवं 164 के तहत दर्ज रिकार्डों पर आधारित है। गवाह यह रिकार्ड कराने के लिए सामने आए कि चिदंबरम उन पर कोर्ट में पेश नहीं होने का दबाव डाल रहे हैं।' सीबीआइ ने कहा है कि जांच में पता चला है कि कार्ति चिदंबरम ने अपनी कंपनी एएससीपीएल के माध्यम से अन्य छह कंपनियों से पैसे लिए। इन कंपनियों को एफआइपीबी की मंजूरी दी गई थी।

सारधा-रोजवैली कांड में नौ पुलिस अफसरों को नोटिस

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- आइपीएस दमयंती सेन और वकार रजा से होगी चार नवंबर के बाद पूछताछ

अरबों रुपये के सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटालों की जांच कर रही सीबीआइ ने अब आइपीएस दमयंती सेन और वकार रजा समेत नौ पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से चार नवंबर से बाद पूछताछ की जाएगी। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त व मौजूदा डीआइजी (सीआइडी) राजीव कुमार की अगुआई में सारधा व रोजवैली कांड की जांच के लिए गठित एसआइटी में बतौर जांच अधिकारी वह शामिल थे। सीबीआइ कई बार राजीव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। यह पहला मौका होगा, जब दमयंती सेन व वकार रजा से पूछताछ करेगी।

गौरतलब है कि सारधा और रोजवैली चिटफंड कांड का पर्दाफाश होने और उनमें सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं के अलावा कोलकाता पुलिस के आलाधिकारियों का नाम सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। पिछले दिनों कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की कोशिश करने वाली सीबीआइ के अधिकारियों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार तक कर लिया था। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने-सामने आ गई थीं। उसके बाद से लगातार सीबीआइ राजीव कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने को निचली अदालत से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में बार-बार अपील करती आई है। अदालत की ओर से राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाए जाने के बाद सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक महीने तक जगह-जगह छापामारी भी की थी, लेकिन पकड़ नहीं सकी। बाद में राजीव कुमार ने खुद अदालत जाकर समर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत ने फिर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नहीं की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई : शाह

अहमदाबाद, एजेंसियां : केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने शासनकाल में उसने आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया।

यहां एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस के दौरान मौनी बाबा (मनमोहन सिंह) प्रधानमंत्री थे। उस समय आतंकी देश में आते थे और हमारे सैनिकों को मार डालते थे। पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों पर स्ट्राइक करके 10 दिनों में कार्रवाई की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि देश सुरक्षित रहे।' गृह मंत्री ने कहा, 'हमने देश के कई हिस्सों में सकारात्मक बदलाव किए। हमने अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किया और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। अब कश्मीर में विकास के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस सांसदों ने संसद में कहा था कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी क्योंकि यह अनुच्छेद (370) हटा दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिना एक भी गोली चलाए कश्मीर में शांति है। अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई गई है। कश्मीर शांतिपूर्ण तरीके से विकास की राह पर है।' नागरिक सुविधाओं के लिए भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि जिन्होंने देश पर 70 साल शासन किया, वे लोगों को आधारभूत सुविधाएं (स्वास्थ्य, सिलेंडर, शौचालय, आवास) भी उपलब्ध नहीं करा पाए।

- पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिन में कार्रवाई की
- कश्मीर शांतिपूर्ण तरीके से विकास की राह पर है

गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अहमदाबाद में 800 करोड़ की लागत से तैयार विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (बाएं) और डिप्टी सीएम नितिन पटेल और अन्य नेता उपस्थित रहे। प्रेट्र

बोनस पर जब पहले की धान की खरीद तो केंद्र को अब क्या दिक्कत : भूपेश

नईदुनिया, रायपुर

- सीएम ने कहा, 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, राज्यपाल को दिया धन्यवाद

छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने बोनस देने वाले राज्यों से सेंट्रल पूल में धान खरीदी पर रोक लगा दी है। केंद्र के इस निर्णय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में पिछले दो साल बोनस देने के बाद भी धान की खरीदी की गई, ऐसे में अब केंद्र को क्या दिक्कत आ रही है।

भूपेश ने कहा कि सिर्फ सरकार बदलने से नियम बदलना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को नियम शिथिल करके छत्तीसगढ़ का धान खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दो बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात की थी। हमने केंद्र से धान खरीदी का आग्रह किया। राज्यपाल को धन्यवाद दूंगा। मैंने शुक्रवार को उनसे कहा था कि आप भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और शनिवार उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री से फिर मिलने की कोशिश करूंगा और किसानों की हालत से रूबरू कराऊंगा। उन्होंने भाजपा सांसदों, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और धान की खरीदी तय कराएं। बघेल ने सांसद सुनील सोनी के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें सोनी ने कहा था कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र क्या पीएम मोदी के भरोसे तैयार किया था। बघेल ने कहा कि हमने मोदी के भरोसे घोषणा पत्र तैयार नहीं किया था। लेकिन केंद्र सरकार को अन्य राज्यों से खरीदी करती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ से भी करे। क्या सोनी किसान विरोधी हैं।

राज्यपाल उइके लिखेंगी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र

धान खरीदी के मसले पर केंद्र सरकार से मांगी गई रियायत पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी अपना सैद्धांतिक समर्थन दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का भी जिक्र किया है।

साझा सूचना और संचार तंत्र पर सेनाएं करेंगी मंथन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भविष्य में होने वाले आधुनिक युद्धों में तीनों सेनाओं के बीच साझा संचार प्रणाली और संचार समन्वय विकसित करने के इरादे से रक्षा मंत्रालय जल्द ही राजधानी दिल्ली में सूचना और संचार तंत्र पर गोष्ठी का आयोजन करेगा। सेना के सिग्नल कोर और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित डेफकॉम गोष्ठी सुरक्षा बलों, अकादमिक जगत, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। डेफकॉम 2019 का विषय 'कम्युनिकेशन ऐज ए डिसाइसिव कैटालिस्ट फॉर ज्वॉइंटनेस' रखा गया है। गोष्ठी में तीनों सेनाओं के लिए आंतरिक संचार के लिए एक बेहतर संयुक्त संचार ढांचा बनाने पर भी चर्चा होगी। जिससे समय समय पर तीनों सेना आपस में एक सुरक्षित और प्रभावशाली संचार तंत्र का विकास कर सकेगी। कार्यक्रम में संचार की नई तकनीक की प्रदर्शनी भी दिखाई दे सकती है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकार मानते हैं कि आधुनिक समय में होने वाले युद्धों में सूचना एवं संचार तकनीक ही निर्णायक भूमिका में रहेगी। सशस्त्र सेनाएं भविष्य में तभी मजबूत होकर उभर सकेंगी जब वे सूचना पर अपना वर्चस्व बना कर रख पाएंगी।

किसानों को 'काली दिवाली' मनाने के लिए किया जा रहा मजबूर : सोनिया

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को काली दिवाली मनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि खरीफ की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से औसतन 22.5 फीसद से कम पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का दोहरा शोषण रोका जाना चाहिए।

दिवाली से पहले एक बयान जारी कर सोनिया ने मोदी सरकार पर लागत से 50 फीसद अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार साल दर साल कुछ बिचौलियों को फायदा पहुंचा रही है और किसानों के करोड़ों रुपये लूट रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह खरीफ फसलों को बेचा जा रहा है उससे किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। जबकि सरकार का राजधर्म किसानों का शोषण रोकना है। उन्होंने कुछ खरीफ फसलों के नाम भी गिनाए जिनमें दालें, सूरजमुखी, ज्वार और बाजरा शामिल हैं। सोनिया ने कहा, एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने खाद पर चार फीसद, कृषि उपकरणों पर 18 फीसद और कीटनाशकों पर 18 फीसद जीएसटी लगा दिया है तो दूसरी तरफ डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है।

हरियाणा में बदलाव में देरी से हुआ नुकसान : **थरूर**: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्वीकार किया है कि मई में हुए आम चुनावों में हार के बाद पार्टी लापरवाह हो गई थी जिसकी वजह से हरियाणा में राज्यस्तरीय बदलाव करने में देरी हुई। अगर यह छह महीने पहले हो गए होते तो हालिया चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हो सकता था।

- एमएसपी से औसतन 22.5 फीसद कम पर बिक रही खरीफ की फसल

सोनिया गांधी। फाइल

2017 में देश में बच्चों के खिलाफ रोजाना 350 अपराध हुए

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में 2017 में बच्चों के खिलाफ रोजाना करीब 350 अपराध हुए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस मामले में दो शीर्ष राज्य बनकर उभरे हैं। बाल अधिकार निकाय सीआरवाई ने यह जानकारी दी है। चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) ने कहा है कि हाल में जारी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डाटा में जानकारी सामने आई है कि 2016-2017 के बीच बच्चों के खिलाफ अपराध में 20 फीसद वृद्धि हुई। अपराध में कुल वृद्धि 3.6 फीसद ही हुई। इसमें कहा गया है, 'एनसीआरबी डाटा बताता है कि 2007 से 2017 के बीच बच्चों के खिलाफ अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस एक दशक के दौरान यह 1.8 फीसद से बढ़कर 28.9 फीसद पर पहुंच गया।' दो साल बाद भारत में अपराध पर जारी एनसीआरबी डाटा में बताया गया है कि बच्चों के खिलाफ 2016 में 1,06,958 अपराध हुए थे। 2017 में 1,29,032 अपराध हुए।

बच्चों के खिलाफ 1900 अपराधों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुए। दोनों राज्यों में 14.8 फीसद अपराध हुए हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा 73.9 फीसद वृद्धि दर्ज हुई जबकि मणिपुर में 2016 और 2017 के बीच 18.7 फीसद की कमी आई।

उपलब्धि

चुनाव प्रबंधन के लिए देश में बना मॉडल, माओवाद प्रभावित राज्य होने के बावजूद आम या उपचुनाव किसी में नहीं हुआ पुनर्मतदान

छत्तीसगढ़ ने पुनर्मतदान मुक्त राज्य बन रचा कीर्तिमान

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ ने देश में एक बार फिर पुनर्मतदान मुक्त राज्य होने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी। चाहे वह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हों या दंतेवाड़ा व चित्रकोट का उपचुनाव। सभी तरह के चुनावों में प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है। कुशल चुनाव प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पूरे देश में मॉडल के रूप में उभरा है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का ऐसा इकलौता राज्य है, जहां मतदाता सूची की कोई शिकायत नहीं आई। चुनाव के दौरान ईवीएम लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। मतदान के दौरान तकनीकी रूप से सबसे कम ईवीएम को बदलने की आवश्यकता पड़ी। कोई भी नक्सली वारदात नहीं हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान हुआ। सीईओ सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों का श्रेय टीम भावना से किए गए कार्य को दिया है।

दिव्यांग, बुजुर्ग पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकेंगे मतदान

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। सरकार ने शनिवार को यह कहा है। इस कदम से मतदान फीसद बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में सशस्त्र बलों और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान होता है। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को गैरहाजिर मतदाता सूची में लाने की अनुमति दी कई है। अनुपस्थित मतदाता ऐसे व्यक्तियों द्वारा मतदान किए जाने को दर्शाता है जो मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों वर्गों में वैसे लोग हैं जो मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने में असमर्थ हैं। इससे इन दोनों वर्गों के लोग आसानी से मतदान कर सकेंगे और मतदाता फीसद में भी वृद्धि होगी। मतदान अधिकारी वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति की स्थिति में फार्म 13ए में अनुपस्थित मतदाता को सत्यापित करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 60.14 फीसद मतदाताओं ने ई-पोस्टल बैलट से मतदान किया जबकि 2014 के आम चुनाव में यह आंकड़ा मात्र चार फीसद था।

छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुरूप बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल के चलते किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को बदलने की नौबत नहीं आई। मतदान दलों के निर्धारित गंतव्य स्थलों में रवानगी के दो घंटे पहले प्री-पैक्ड पोलिंग मैटेरियल्स सुरक्षित रखे गए, जिससे समय की बचत हुई।

एक वर्ष में विधानसभा, लोकसभा के साथ दो उपचुनाव : राज्य में पिछले नवंबर से अब तक विधानसभा और लोकसभा के मुख्य चुनाव के साथ दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। नवंबर- दिसंबर 2018 में विधानसभा, अप्रैल- मई 2019 में आम चुनाव, सितंबर- अक्टूबर 2019 में दंतेवाड़ा और चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव शामिल है।

निकाय चुनाव ईवीएम से कराने की भाजपा की राज्यपाल से गुहार : छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराने की गुहार लेकर भाजपा राज्यपाल के पास पहुंची। भाजपा ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि सरकार बैलेट से चुनाव करा कर लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र रच रही है। सांसद सुनील सोनी ने राज्यपाल से कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के जीतने का अंतर बहुत कम होता है और मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने पर काफी सारे मत अवैध घोषित हो जाते हैं। इसका चुनाव परिणामों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जीतने वाले प्रत्याशी का मतांतर अवैध घोषित मतपत्रों से काफी कम होता है। ऐसे समय चुनाव परिणाम की वैधता भी संदिग्धता की दायरे में आती है। राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल आदि शामिल रहे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी